भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3060

जिसका उत्तर 11 मार्च, 2026 को दिया जाना है ।

20 फाल्गुन, 1947 (शक)

इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 पर किया गया व्यय

3060. एडवोकेट प्रिया सरोजः

श्री पुष्पेंद्र सरोजः

श्री आनंद भदौरियाः

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने फरवरी, 2026 के महीने के दौरान दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन किया है और यदि हां, तो शिखर सम्मेलन के दौरान हितधारकों के समक्ष लॉजिस्टिक संबंधी समस्याओं के कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के आयोजन पर सरकार द्वारा आयोजन स्थल, रसद, प्रचार, परामर्श और आतिथ्य व्यय पर कुल कितना व्यय किया गया है;

(ग) सरकार द्वारा प्रायोजित या वित्तपोषित प्रतिभागियों की संख्या कितनी है और प्रति प्रतिभागी कितना व्यय किया गया है;

(घ) आयोजन के लिए उपयोग की गई निधि का स्रोत क्या है और क्या व्यय बजटीय आवंटन या पुनर्विनियोजन के माध्यम से पूरा किया गया था;

(ङ) शिखर सम्मेलन के लिए प्राप्त प्रायोजन, निजी भागीदारी या कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) योगदान, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है;

(च) इंडिया एआई मिशन के संबंध में सम्मेलन के लिए निर्धारित उद्देश्यों, महत्वपूर्ण परिणामों का ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या नीति, नवाचार या निवेश परिणामों पर शिखर सम्मेलन के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई लागत-लाभ या आयोजन-पश्चात मूल्यांकन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत इंडिया एआई मिशन कृषि, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में समावेशी एआई अपनाने के लिए सम्मेलन की चर्चाओं को ठोस नीतियों में किस प्रकार परिवर्तित करेगा?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ज): माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप, सरकार प्रौद्योगिकी के विकास और उपयोग का लोकतंत्रीकरण कर रही है। वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने और अंततः विभिन्न क्षेत्रों में जीवन को बेहतर बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

भारत-एआई इम्पैक्ट समिट 2026

भारत ने नई दिल्ली में 16-21 फरवरी 2026 तक भारत-एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी की। पहली बार, ग्लोबल एआई शिखर सम्मेलन श्रृंखला ग्लोबल साउथ में हुई। यह बदलाव एक अधिक समावेशी वैश्विक एआई संवाद की ओर एक व्यापक कदम का संकेत देता है।

शिखर सम्मेलन एक ऐतिहासिक वैश्विक अभिसरण के रूप में संपन्न हुआ, जिसने भारत को कृत्रिम बुद्धिमत्ता नवाचार, शासन, साझेदारी और समावेशी विकास के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित किया।

किसी भी विकासशील राष्ट्र द्वारा आयोजित अपनी तरह का सबसे बड़ा पांच दिवसीय मेगा-इवेंट, "सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय" थीम के तहत सरकारों, उद्योग, शिक्षाविदों, नागरिक समाज और स्टार्टअप के अग्रणी समूहों को एक साथ लाया गया।

उद्देश्य, परिमेय परिणाम और डिलिवरेबल्स

शिखर सम्मेलन की चर्चाओं को सात विषयगत "चक्रों" मानव पूंजी, समावेशन, सुरक्षित और विश्वसनीय एआई, लचीलापन, नवाचार और दक्षता, एआई संसाधनों का लोकतंत्रीकरण, और आर्थिक विकास और सामाजिक भलाई के लिए एआई के इर्द-गिर्द संरचित किया गया था।

शिखर सम्मेलन का उद्देश्य इंडियाएआई मिशन के लक्ष्यों के अनुरूप संवाद, स्वैच्छिक प्रतिबद्धताओं और सहयोगात्मक पहलों को सुविधाजनक बनाना है।

इनमें एआई बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, नवाचार को बढ़ावा देना, कौशल पहल का विस्तार करना, स्थिरता सुनिश्चित करना और जिम्मेदार एआई पद्धतियों को आगे बढ़ाना शामिल है।

शिखर सम्मेलन के दौरान घोषित प्रमुख पहलों और परिणामों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- शिखर सम्मेलन के दौरान सात विषयगत कार्य समूहों द्वारा किए गए कार्यों को स्वीकार करते हुए घोषणा के साथ 92 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट घोषणा का समर्थन किया गया
- नई दिल्ली फ्रंटियर एआई इम्पैक्ट प्रतिबद्धताओं पर 13 प्रमुख मॉडल प्रदाताओं द्वारा हस्ताक्षर किए गए
- 7 कार्य समूहों में 12 डिलिवरेबल्स, प्रत्येक डिलिवरेबल के लिए 20+ देशों के व्यक्तिगत समर्थन के साथ [पिछले शिखर सम्मेलनों की तुलना में काफी अधिक]
    - 30+ देशों में 80+ इम्पैक्ट स्टोरीज के साथ ग्लोबल एआई इम्पैक्ट कॉमन्स का शुभारंभ
    - अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के साथ साझेदारी में इक्विटेबल एआई ट्रांजिशन प्लेबुक का विमोचन
    - लचीले, अभिनव और कुशल एआई के लिए स्वैच्छिक मार्गदर्शक सिद्धांतों पर हस्ताक्षर, 20+ देशों द्वारा समर्थन किया गया
    - एआई के युग में रीस्किलिंग के लिए स्वैच्छिक मार्गदर्शक सिद्धांतों पर हस्ताक्षर, 24 देशों द्वारा समर्थित
    - 25 देशों और अंतर्राष्ट्रीय देशों के समर्थन से एआई के लोकतांत्रिक प्रसार के लिए चार्टर को अपनाना
    - लचीले एआई बुनियादी ढांचे को आगे बढ़ाने के लिए प्लेबुक का विमोचन
    - एआई गवर्नेंस पर मार्गदर्शन नोट जारी करना, 22 देशों द्वारा समर्थित
    - औपचारिक लॉन्च से पहले 23 भागीदार देशों के साथ विश्वसनीय एआई कॉमन्स की घोषणा
    - एआई के माध्यम से समावेशन को आगे बढ़ाने के लिए गठबंधन की घोषणा की गई, 21 देशों और यूनिसेफ द्वारा इसका समर्थन किया गया
    - शुरुआत में 20 भागीदार देशों के साथ विज्ञान संस्थानों के लिए एआई नेटवर्क का शुभारंभ
    - फ्रांस और यूनेस्को के साथ साझेदारी में रेजिलिएंट एआई चैलेंज का शुभारंभ

- एआई उत्तरदायित्व अभियान - वैश्विक रिकॉर्ड: भारत ने 2.5 लाख से अधिक मान्य प्रतिज्ञाओं के साथ "24 घंटों में एआई जिम्मेदारी अभियान के लिए प्राप्त सबसे अधिक प्रतिज्ञाओं" के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सफलतापूर्वक हासिल किया।
- उच्चतम प्रभाव वाले एआई परिनियोजन का दस्तावेजीकरण करने वाली छह वैश्विक केसबुक जारी की गईं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
    - स्वास्थ्य में एआई (डब्ल्यूएचओ के साथ)
    - ऊर्जा में एआई (आईईए के साथ)
    - लैंगिक सशक्तिकरण में एआई (संयुक्त राष्ट्र महिला के साथ)
    - कृषि में एआई (महाराष्ट्र सरकार के साथ, विश्व बैंक द्वारा समर्थित)
    - शिक्षा में एआई (सीएसएफ और एकस्टेप फाउंडेशन के साथ)
    - एक्सेसिबिलिटी में एआई (एलिम्को, आईआईआईटी-बैंगलोर और चेंजइंक फाउंडेशन के साथ)
- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा एआई इम्पैक्ट स्टार्टअप बुक भी लॉन्च की गई, जो भारत के एआई और डीप-टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम में अंतर्दृष्टि प्रस्तुत करती है।

शिखर सम्मेलन में एआई मूल्य श्रृंखला में निवेश प्रतिबद्धताओं की घोषणाएं भी हुईं, जिसमें बुनियादी ढांचे, फाउंडेशन मॉडल, हार्डवेयर और अनुप्रयोगों में 250 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के अपेक्षित निवेश शामिल हैं।

बड़ी भारतीय कंपनियों द्वारा एआई के लिए तैयार डेटा केंद्रों का विस्तार करने के लिए साझेदारी के साथ-साथ एआई बुनियादी ढांचे और डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में सामूहिक रूप से सौ अरब डॉलर से अधिक का निवेश करने की योजना की घोषणा की गई।

वैश्विक उद्यम पूंजी फर्मों द्वारा एआई नवाचार का समर्थन करने के लिए बहु-अरब डॉलर के निवेश का वादा किया, जबकि एक अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनी ने संबद्धता, भारत में एक एआई हब और लाखों लोक सेवकों और छात्रों तक पहुंचने वाले बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण पहल में महत्वपूर्ण निवेश की घोषणा की गई।

शिखर सम्मेलन ने एआई इकोसिस्टम में संवाद, साझेदारी और निवेश घोषणाओं के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया। शिखर सम्मेलन को सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि या रोजगार सृजन का अनुमान लगाने के लिए एक तंत्र के रूप में तैयार नहीं किया गया था।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत इंडियाएआई मिशन ने अपने 7 स्तंभों के माध्यम से शिखर सम्मेलन की व्यापक चर्चाओं को आगे बढ़ाने, एआई स्टार्टअप और अनुसंधान संस्थानों का समर्थन करने, कंप्यूट बुनियादी ढांचे तक पहुंच को मजबूत करने और कृषि, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में अच्छे समाधानों के लिए एआई को सक्षम बनाने और बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाने की योजना बनाई है।

मिशन सरकार, उद्योग, शिक्षाविदों और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के बीच सहयोग को भी बढ़ावा देता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एआई को अपनाना राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और सामाजिक जरूरतों के अनुरूप बना रहे।

9 मार्च 2026 तक 65 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है।

लगभग 400 प्रतिभागियों को सरकारी सहायता प्रदान की गई। इनमें देशों के प्रतिनिधि, अनुसंधान संगोष्ठी के प्रतिभागी और नवाचार चुनौतियों के प्रतिभागी शामिल थे।

*****